MR. CHAIRMAN: Next question.

National Highway Development Programme

*63. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:†

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the extent to which the targets regarding National Higway Development Programme have been achieved during the Sixth Five Year Plan period stating the shortfall, if any; and

(b) the names of the State which have failed to achieve their targets and what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The expected achievements against targets are 81 per cent to 100 per cent in respect of various major road items and 83 per cent in respect of major bridge works. The shortfall in targets is in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The principal reasons for shortfalls are Land Acquisition problems, encroachments litigations, unexpected foundation problems, unprecedented floods causing dislocation, chronic labour problems, contractual problems and difficulties in finding suitable contractors for works in far flung areas.

श्री राम नरेश कुशवाहा : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 81 और 83 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा हिसाब है जिससे इतना लक्ष्य पूरा हो गया कि 2700 करोड़ रुपये के पूरे प्लान में लगभग 660 करोड़ रुपया ही खर्च होने वाला है योजना के अन्त तक, उसमे एक चौथाई कर के 81 प्रतिशत लक्ष्य कैसे पूरा हो जायगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो एस्टीमेट 80 में बना था उसमें कीमतें बढ़ने की वजह से निर्माण में कितनी कमी हो गयी ? माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें।

श्री जैड० आर० अन्सारी : सभापति जी 666 करोड़ छठी पंचवर्षीय योजना में रोड्स से सेक्टर में रखा गया था। मैंने जो आंकड़े बताये है, परसेंटेज बताया है वह इस बुनियाद पर बताया है कि मिसिंग लिंक्स 196 किलोमीटर का टार्गेट था छठी पंचवर्षीय योजना में, उसमें सम्भावना है कि 170 किलोमीटर बना लेंगे, 26 किलोमीटर रह जायगा, इस तरह से 87 परसेंट की उपलब्धि होगी। इसी तरह से सिगल लेन रोड्स को दो लेन रोड्स में परिवर्तित करने के लिए 4224 कलोमीटर का टारगेट था जिसमें 4224 किलोमीटर बन गया, इसमें हंड्रेड परसेंट की उपलब्धि हो गई। इसी तरह से ऐक्जिस्टिंग कमजोर डबल लाइन रोड्स का टारगेट 2298 किलोमीटर था जिसमें 2288 किलोमीटर बन गया, इसमें उपलब्धि 102 परसेंट हो गई। जो चार लाइन और 6 लाइन की रोड्स को वाइडन करने का टारगेट 130 किलोमीटर का था उसमें 105 किलोमीटर बन गया, 25 किलोमीटर रह गया। इस तरह से इसमें हमारी उपलब्धि 81 प्रतिशत की है।

बाई-पास 52 बनने थे जिनमें से 42 बन जाने की संभावना है, इसलिए इसमें उपलब्धि 81 प्रतिशत है। बड़े पुल 103 बनाने का टारगेट था छठी पंचवर्षीय योजना में जिसमें 86 पुल बन चुके है, 17 बाकी रह गए हैं। इस तरह से हमारी उपलब्धि करीब 83 प्रतिशत हो जाएगी। ये सब जो हमने आंकड़े दिए है, इस बुनियाद पर दिए हैं।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Naresh Kushawaha.

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन प्रदेशों को कितना रुपया दिया गया था और कितना खर्च हुआ और किस प्रदेश में कितना लक्ष्य पूरा हुआ ?

श्री जैड० आर० अंसारी : सभापति जी, मैंने आपसे अर्ज किया कि 660 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में इस सेक्टर में रखा गया था रोड्स और ब्रिजेज के लिए और 660 रुपये के बजाय हमको 620 करोड़ रुपया मिला है, उसमें मने यह बनाया है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : श्रीमन्, मैंने स्टेटवाइज पूछा किस-किस स्टेट में कितना अलाट किया गया और कितना खर्च हुआ ?

MR. CHAIRMAN: No, do not answer. The question will not be answered.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, उन्होंने सवाल किया कि कितना स्टेटवाइज खर्च हुआ, इसका जवाब नहीं दिया गया क्वैश्चन क्या पूछें ? आप सदस्यों को प्रोटेक्शन दीजिए : . . . (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : हमने गोल-माल सवाल नहीं पूछा, निश्चित सवाल पूछा और उसका निश्चित जवाब मिलना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।

MR. CHAIRMAN: I have heard the answer. He has given all the facts in his possession. If you want further information, you can ask for Half-an-Hour discussion or something like the kind. There is the procedure laid down for this.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, मैं चाहूंगा कि आप सदस्य की रक्षा करें। अगर इन्होंने स्टेटवाइज ऐक्सपेंडीचर का सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि हाफ ऐन अवर डिस्कशन करो। . . . (**व्यवधान**)

श्री रामनरेश कुशवाहा : हाफ ऐन अवर डिस्कशन तो जवाब पर होता है। यह तो निश्चित सवाल पूछा है, उसका निश्चित जवाब होना चाहिए, गोलमाल जवाब आप दिया करेंगे ? . . . (**व्यवधान**)

श्री रामानन्द यादव : क्वैश्चन में स्टेटवाइज नहीं है। . . . (**व्यवधान**)

SHRI VIRENDRA VERMA: Kindly see (b) part of the question.

MR. CHAIRMAN: Yes, I have read. Yes, Mr. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि लक्ष्य पूरे न होने के कई कारण हैं। इसमें दो कारण हैं। एक तो भूमि अधिग्रहण की समस्या और दूसरे गैर-कानूनी कब्जा। तो मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि भूमि अधिग्रहण और गैर-कानूनी कब्जे के सिलसिले में एक कारण उन्होंने मुकदमेबाजी बताया है, मेरा सवाल यह है कि जो कठिनाइयां आ रही है, जिन से आपकी योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होता है या योजनाएं पूरी नहीं हो पातीं तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या द्रुतगामी कदम आप उठा रहे हैं ?

श्री जैड० आर० अंसारी : सभापति जी, यह जरूर है कि कुछ ऐसी कठिनाइयां आ रही हैं जिनकी वजह से हमार प्रोजक्ट्स में विलम्ब होता है। इसी लिए मरकज ने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि वह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में अलग से लैंड एक्वीजीशन आफीसर मुकर्रर करें ताकि सड़कों और ब्रिजों के लिए जो लैंड एक्वीजीशन करना होता है उसको वह अलग से देखें। और जो नाजायज कब्जे हैं उनको दूर करने के लिए पी० डब्लू० डी० अलग से आफीसर मुकर्रर करे। इसी तरह से और दूसरे कदम उठाये गये हैं।

Construction projects are now being sanctioned only after the land required for the project has been acquired.

जब लैंड एक्वायर हो जाती है उसके बाद प्रोजेक्ट को हम सेंक्शन करते हैं। ये कुछ कदम हैं जिनको उठा रहे हैं ताकि जमीन पहले मिल जाय और हमारे प्रोजक्ट्स में डिले न हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने दो सवाल पूछे थे। लैंड एक्वीजीशन का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गैर-कानूनी कब्जे वाले सवाल का उत्तर नहीं दिया।

MR. CHAIRMAN: You have not heard the answer. The hon. Minister has said that there is delay in land acquisition and he is appointing more Land Acquisition Officers to expedite it. Yes, Mr. Nirmal Chatterjee.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : ऐसे भी केसेज होते हैं जहां लोग जबरदस्ती आकुपाई कर लेते हैं, लैंड एक्वीजीशन का सवाल नहीं है।

MR. CHAIRMAN: This is exactly what he said. You refer to the answer. Mr. Minister, in one sentence you can repeat the answer.

श्री जैड० आर० अंसारी : हमने स्टेट्स को यह भी कहा है कि वे पी० डब्लू० डी० में अलग से लैंड एक्विजेशन आफीसर भी मुकर्रर करें ताकि केसेज का डिस्पोजल आसानी से कर दिया जाय।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Mr. Chairman, as part of the National Highway Development Programme, in the Third Five Year Plan a project was taken up. Its name is Belgoria Expressway linking up National Highway No. 2 and National Highway No. 34. It was to have been completed in the course of the Third Five Year Plan—i.e. by 1965. Now there is very little problem of land acquisition there. It seems lack of funds, lack of enthusiasm for the project at the Central level is what is delaying it. Now a delay on this link expressway, which is in the Central sector, means that from Calcutta, if you want to visit even Rajghat, the memorial to Gandhiji, then you have to be on the way deadlocked for hours together. Now I want to know whether the Minister is aware that such a project exists which was to have been completed in 1965, but still continues in its bullock-cart movement till the year 1984. And there is no sign of its being completed. My simple question is, when do you propose to complete that project before there is a total break-down on this highway connecting Calcutta city?

SHRI Z. R. ANSARI: I require notice, because this is a general question.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Would he send me a reply in writing to the specific question?

MR. CHAIRMAN: Yes, he will send a reply.

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में मंत्री महोदय ने बताया कि 81 परसेंट टारगेट पूरा हो गया है। उन्होंने जो अपने उत्तर में राज्यों का जिक्र किया उसमें बिहार का भी जिक्र किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बक्सर में जो गंगा नदी का पुल बना है, आरा टू पटना, यह नेशनल हाईवे है तो क्या यह छठी पंचवर्षीय योजना में था और अगर था तो इस काम में अभी कितनी तरक्की हुई है और यह काम कब तक पूरा होगा?

श्री जैड० आर० अन्सारी : यह सवाल आपने सड़क के बारे में पूछा है या ब्रिज के बारे में पूछा है?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सड़क के बारे में।

MR. CHAIRMAN: You know the answer yourself. You have been a Minister. (*Interruptions*).

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अगर इनके पास अभी जवाब नहीं है तो बाद में दे देंगे।

SHRI Z. R. ANSARI: Buxur-Arra-Patna road you are talking about. It is not a national highway. Arra-Patna is a national highway. All important project works are in progress.

SHRI A. P. SHARMA: How can it be? Arra to Patna? Or Buxur? It goes to Ghazipur, Balia and all these places. (*Interruptions*).

SHRI THANGABAALU: Sir, there is an impression that southern States are being neglected in regard to national highways development programme. I want to know specifically from the hon. Minister how much money has been allocated for the Southern States in the National Highway Development programme. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You should not take note of the interruptions. Please *put your question.*

SHRI THANGABAALU: Will the hon. Minister state how much money has been allocated for southern States particularly and how many works have been implemented?

SHRI Z. R. ANSARI: Sir, we have State-wise length about the national highways. If the hon. Member is interested I can read out.

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI Z. R. ANSARI: I can read out the kilometres in the southern States.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He wants to know how much has been allocated for Tamil Nadu, Kerala, Karnataka—southern States. (*Interruptions*). All right, you send him the reply. The Minister will send a reply. Next question.

Development of Ayurvedic drug 'Malcurin'

*64. PROF B. RAMACHANDRA RAO:†

SHRIMATI USHA MALHOTRA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether a new Ayurvedic drug known as 'MALCURIN' has been developed by the Central Council for Research in Ayurveda and Siddha;

(b) whether this drug has been found to be effective even in cases where malaria parasites have developed resistance to chloroquin; and

(c) whether Government have taken any steps to produce this drug on a large scale and make it available to the public at reasonable prices?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) This is a *brand name of a product of an Ayur*vedic medicine developed by the Central Council of Research in Ayurveda and Siddha under code name AYUSH-64.

(b) Trials by the Central Council of Research in Ayurveda and Siddha have shown that AYUSH—64 is effective against Plasmodium Vivax. However, no studies have yet been carried out as to the efficacy of this drug against Malaria parasites resistant to Chloroquin.

(c) The National Research Development Corporation, a Government of India Undertaking under the Ministry of Science and Technology, have entered into Agreement with 8 firms to manufacture the drug, of which 4 have already gone into production.

PROF. B. RAMACHANDRA RAO: Sir, I would ask only one question because time is short and my colleague, Mrs. Usha Malhotra, might like to put a question. I am very glad that an ancient herbal drug known for its efficacy against malaria has at last been studied by the Central Council and is made available under the code name Ayush-64. This is produced as Malcurin by Goodman's Company. The Minister has stated that it is effective against Plasmodium Vivax which is a common ma-

†The question was actually asked on the floor of the House by Prof. B. Ramachandra Rao.